International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(I), April - June, 2021, pp.166-170

मानव विकास के विविध आयामः राजस्थान राज्य के संदर्भ में

डायालाल सांखला*

सार

मानवीय विकास एक विस्तृत अवधारणा है। मानव विकास, मानवीय विकास की अवधारणा से सम्बन्धित है। जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्र के लोगों के सार्थक जीवन जीने की परिस्थितयों का निर्माण करना है। मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मानव जीवन के विभिन्न आयामों के साथ ही दीर्घायु, ज्ञान एवं सम्मानजनक जीवन यापन के मात्रात्मक तत्वों पर केन्द्रित एक समग्र सूचकांक है। 'मानव कल्याण' की प्रगति के पथ को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) व्यापक रूप से स्वीकार्य मापक हैं। जहाँ उपलब्धियों के स्तर को मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है, वहीं अभावों के स्तर को मानव निर्धनता सूचकांक द्वारा मापा जाता है। 2018 में भारत का विश्व के 189 देशों में मध्यम स्तर के मानव विकास सूचकांक 0.640 के साथ 130 वां स्थान है। देश में राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग कि.मी. में फैला है। राजस्थान का पहला मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2002 में जारी किया गया था। इसका मुख्य विषय ''वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना'' था। राज्य सरकार मानव विकास के विभिन्न आयाम हेतु सीधे मानव क्षमताओं को बढ़ाने के अन्तर्गत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एक स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने की क्षमता, शिक्षा तथा प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को सुधारने एवं बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इन कार्यक्रमों के द्वारा सरकार निरन्तर मानव विकास के विविध आयाम को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है।

कुंजी शब्दः *मानव विकास, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, मानव विकास प्रतिवेदन।*

प्रस्तावना

मानव विकास दृष्टिकोण में लोगों को विकास के एजेण्डा के केन्द्र में रखा जाता है, जबकि आर्थिक वृद्वि एवं समृद्वि कोविकास के साधन के रूप में माना जाता है न कि साध्य के रूप में। मानव विकास दृष्टिकोण का प्रारम्भिक विचार यह है कि विकास का उदेश्य मानव जीवन में सुधार करना है न कि केवल आय में वृद्धि करना है बल्कि उन कार्यों की सीमाओं काभी विस्तार करना है जो एक व्यक्ति करना चाहता है एवं कर सकता है जैसे कि स्वस्थ एवं सुपोषित होना, ज्ञानोपार्जन एवंसामुदायिक सहभागिता। मानव विकास की अवधारणा 1980 के दशक के उतरार्द्ध में विकसित हुई जो कि डॉ. अमर्त्य सेन एवं डॉ. महबूब उल हक की बुनियादी अवधारणा पर आधारित है। मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) मानव जीवन केविभिन्न आयामों के साथ ही दीर्घायु, ज्ञान एवं सम्मानजनक जीवनयापन के मात्रात्मक तत्वों पर केन्द्रित एक समग्र सूचकांक है। 'मानव कल्याण' की प्रगति के पथ को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) तथा मानव निर्धनता सूचकांक (एच.पी.आई.) व्यापक रूप से स्वीकार्य मापक हैं। जहाँ उपलब्धियों के स्तर को मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है, वहीं अभावों के स्तर को मानव निर्धनता सूचकांक द्वारा मापा जाता है।

* सहायक आचार्य, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध,एम.बी.सी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर, राजस्थान।

समग्र मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.), मानव विकास के तीन मूल आयामों का एक एकीकृत सूचक हैः

- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एक स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने की क्षमता को दर्शाती है।
- स्कूली शिक्षा के औसत एवं अनुमानित वर्ष ज्ञानोपार्जन की क्षमता को दर्शाते है।
- प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय एक सम्मानजनक जीवनयापन की क्षमता को दर्शाता है।

मानव विकास का महत्व

किसी देश का आर्थिक विकास उस देश में उपलब्ध मानव पूंजी के स्टॉक तथा संचय की दर पर निर्भर करता है। विकासशील देशों में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इन देशों में विकास के वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाते है तथा वहाँ विकास की दर निम्न रहती है। आज अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस बात के पक्षधर है कि मानव पूंजी में अधिक से अधिक विनियोग किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मानव संसाधन का समुचित विकास किया जा सके। किसी भी देश की जनसंख्या का जितना अधिक हिस्सा शिक्षित कुशल एवं प्रशिक्षित, होकर रोजगार में लगा हुआ है, वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भौतिक पूँजी की अपेक्षा मानव पूंजी को कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि मानवीय साधनों की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का भी विचार था कि "सबसे मूल्यवान पूँजी वह है जो मानव मात्र में विनियोजित की जाये।

वैश्विक मानव विकास प्रतिवेदन

वैश्विक मानव विकास प्रतिवेदन –2018में भारत का विश्व के 189 देशों में मध्यम स्तर के मानव विकास सूचकांक 0.640 के साथ 130 वां स्थान है। इस प्रतिवेदन में अनुसारउद्देश्य निम्न हैः

- सार्वभौमिकता मानव विकास की कुंजी है एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव विकास प्राप्य है।
- व्यक्तियों के विभिन्न समूह अभी भी मूलभूत अभावों से ग्रस्त हैं और उन पर काबू पाने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करते है।
- प्रत्येक के लिए मानव विकास, कुछ विश्लेषणात्मक मुद्दों तथा मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य पर पुनर्व्याख्या पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- नीतियों के विकल्प विद्यमान है और यदि उन्हेंक्रियान्वित किया जाता है तो यह प्रत्येक के लिए मानवविकास प्राप्त करने में सहयोग करेगें।
- उत्कृष्ट बहुपक्षीयवाद के साथ, एक सुस्थापित वैश्विकशासन, प्रत्येक के लिए मानव विकास को प्राप्त करने मेंसहयोग करेगा।

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक त्वरित वृद्धि केलिये अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोले है, जिससे मानव विकास की चुनौतियों यथा गरीबी कम करना, स्वास्थ्य कीस्थितियों मे सुधार एवं मूलभूत सामाजिक सेवाओं तक पहुंच केविस्तार को बदलने में सहयोग मिला हैं।

भारत का मानव विकास प्रतिवेदन

भारत का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन (आई.एच.डी.आर.)वर्ष 2001 में प्रकाशित किया गया था। इसमें मानव विकास केलिए सुशासन (गुड गवर्नेन्स) दृष्टिकोण की पैरवी की गई।द्वितीय भारत मानव विकास प्रतिवेदन –2011''टुवर्ड्स सोशल इन्क्लूजन'', इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च एवं योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011में प्रकाशित किया गया। इसमें यह तर्क दिया गया है किगरीबी में सफलतापूर्वक कमी लाने हेतु आर्थिक वृद्धि की मुख्य आवश्यकता मानव पूंजी एवं मानवीय क्रियाकलापों का विस्तारकरने से है तथा विशेषकर सीमान्त वर्गों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों को एकीकृत कर समावेशन किया जावे।

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मानव विकास सूचकांक मेंवर्ष 1999–2000 से वर्ष 2007–08 (नवीनतम वर्ष, जिसकेलिए अनुमानित किया जा सका है), के बीच 21 प्रतिशत कीवृद्वि हुई है, जबकि राजस्थान में, इसी अवधि के दौरान यहवृद्धि 12 प्रतिशत की रही है।

राज्य मानव विकास प्रतिवेदन

राजस्थान का पहला मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2002 मेंजारी किया गया था। इसका मुख्य विषय ''वैश्वीकरण के युगमें स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना'' था। यह प्रतिवेदन,जहाँ एक ओर कृषि पर केन्द्रित था, वहीं दूसरी ओर इसमेंविभिन्न क्षेत्रों के असंतुलन को भी दर्शाया गया था। इसमेंलैंगिक व स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों को चिन्हित कर विशेषमहत्व दिया गया था। इसमें राजकोषीय सुधार कीआवश्यकता, समष्टि अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं स्थायी मानव विकास व्यूह रचना को प्राथमिकता दी गई थी। राज्य केमानव विकास प्रतिवेदन का अद्यतन वर्ष 2008 में तैयार कियागया था।

राज्य का क्षेत्रवार परिदृश्य

मानव विकास के विभिन्न घटकों की राज्य में वर्तमान स्थितिनिम्नानुसार है:

शैक्षिक उपलब्धियां

शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अन्य सामाजिक क्षेत्रोंयथा–स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, बाल विकास,श्रम इत्यादि को भी प्रभावित करता है। यह आर्थिक वृद्वि तथाविकास को बढाने का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा लोगों केजीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ प्रगति के अवसरभी उपलब्ध कराती हैं। शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थितिजनगणना–2011 के अनुसार, राजस्थान की साक्षरता दर वर्ष2001 की 60.4 प्रतिशत की तुलना में 66.1 प्रतिशत दर्ज कीगई है, इस प्रकार 2001–2011 की अवधि के दौरान साक्षरतामें शुद्ध वृद्धि 5.7 प्रतिशत की दर्ज हुई है। वर्ष 2011 में पुरुषएवं महिला साक्षरता दर क्रमशः 79.2 प्रतिशत एंव 52.1प्रतिशत है। परिणामस्वरुप राज्य में साक्षरता दर के मध्यलैंगिक अन्तराल 2001 से 2011 की अवधि के दौरान 4.7 प्रतिशतघटा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक अन्तराल 5.3 प्रतिशतघटा है।राज्य में प्राथमिक स्तर पर, वर्ष 2013–14 की औसत वार्षिकड्रॉप आउट रेट 8.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 5.02 प्रतिशत हुई है, जबकि भारत में, इसी अवधि के दौरान यह दर 4.3 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत रही है। यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजस्थान का प्राथमिक स्तर पर,शुद्ध नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) वर्ष 2014–15 से 2015–16 की अवधि के दौरान 77.8 प्रतिशत से बढ़कर 79.2 प्रतिशत हो गया है जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 87.4 से थोडा घटकर 87.3 प्रतिशत परहा है। वर्ष 2015–16 में राजस्थान का प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक 0.98 था, जबकि इसी अवधि में भारत के लिए यह 1.03 था।

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं विकास तथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति एवं सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहें हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं तथा कार्यक्रम जैसे सर्वशिक्षा अभियान, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लागु किया गया । केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रम जैसे– स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, शारदे बालिका छात्रावास, निर्माण कार्य, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–8वीं, 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी) कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बालिकाओं पर केन्द्रित अनेक पहल की गई हैं जैसे– साईकिल वितरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित छात्राओं के लिए सावधि जमा प्राप्ति (एफ.डी.आर.), गार्गी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन इत्यादि।

स्वास्थ्य सुविधाएं

राज्य में, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर वर्ष 1998 में 508 था (सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 1997–98 के अनुसार), जो कि वर्ष 2011–13 में घटकर 244 (एस.आर.एस. 2011–13) के स्तर पर आ गया है, जो अभी भी राष्ट्रीय औसत मातृ मृत्यु अनुपात 167की तुलना में अधिक है।2015–16, के अनुसार राज्य में 15–49 आयु की सभी महिलाओं में रक्ताल्पता 46.8 प्रतिशत हैं, जबकि एन.एफ.एच.एस.–ण्ण् (2005–06) में यह 53.1 प्रतिशत था।राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–प्ट (एन.एफ.एच.एस), 2015–16 के अनुसार, राजस्थान में संस्थागत प्रसव 84.0 प्रतिशत है।राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 0–6 आयु वर्ग में लिंगानुपात प्रति हजार बालकों पर केवल 888 बालिकाएं हैं। समग्र वृद्धि के साथ आगे बढ़ने के लिए यह एक ध्यान देने योग्य विषय है।वर्ष 2016 के दौरान, टी.बी. रोगियों की कन्वर्जन दर और इसके निदान की दर क्रमशः 92 प्रतिशत व 87 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान राज्य में कुष्ठ रोग की प्रसार दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.17 रही है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 0.69 रही है।

राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा हाल के वर्षों में अनेक पहल/योजनाएं क्रियान्वित कीगई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पहल/योजनाएं निम्नलिखित हैं : मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, 108 टोल फ्री एम्बुलेंस योजना, निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम,आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.),एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.),कसैंर, मधुमेह, ह्रदयवाहिका रोग तथा आघात रोकथाम एव ंनियत्रंण हेतु राष्ट्रीय कायर्क्रम आदि।

जीवनयापन संबंधी धारणाएं

राजस्थान को उसकी भौगोलिकता, आजीविका, भ–ू पब्रन्धन प्रणली एवं सामाजिक पहचान में अत्यधिक विविधता की विशेषताओं से जाना जाता है यहाँ आय एवं परिसम्पत्तियों कावितरण भी असमान हैं राज्य में कृषि एवं पशपुालन आजीविका के प्रमुख स्त्रोत हैं. तथापि प्रदेश में मानसनू की अनियमितता के कारण कृषि उत्पादन में व्यापक उतार–चढ़ाव हाता है।राज्य में आजीविका के स्तर के आंकलन हेतु, एक निर्धारित अवधि में, प्रति व्यक्ति आय एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। राज्य में, वर्ष 2011–12 से 2017–18 (अग्रिम अनुमान) के दौरान प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर रूपये 57,192 से बढ़कर रूपये 1,00,551 हो गई है एवं स्थिर (2011–12) कीमतों पर रूपये 57,192 से बढ़कर रूपये 76,146 हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 299 लाख श्रमिक है, जिनमें से 244 लाख ग्रामीण क्षेत्रों तथा 55 लाख शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। राज्य में कार्य सहभागिता दर वर्ष 1981 की 36.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 43.6 प्रतिशत हो गई है। जनगणना वर्ष 2011 में, कार्य सहभागिता दर कुल जनसंख्या का 43.6 प्रतिशत थी, यह पुरूषों के लिए 51.5 प्रतिशत व महिलाओं के लिए 35.1 प्रतिशत थी। गत दशक में कार्य शक्ति में 1.5 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

राज्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं : पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, एम्प्लॉयमेन्ट लिंक्ड स्किल ट्रेंनिग प्रोग्राम (ई.एल. एस.टी.पी), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि।

मानव विकास के आयाम

राज्य सरकार मानव विकास के विभिन्न आयामहेतु सीधे मानव क्षमताओं को बढ़ाना के अन्तर्गत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एक स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने की क्षमता, शिक्षा तथाप्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को सुधारने एवं बेहतर बनाने में तथा साथ ही साथ मानव विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण जिसमें मानव सुरक्षा एवं अधिकार, लैंगिक समानता, राजनैतिक एवं सामुदायिकता सहभागिता के लिए आर्थिक विकास के साथ मानव विकास और सतत विकास पर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ बुनियसदी ढांचे के विकास से निवेश दक्षता में वृद्धि होती हैं, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता आती है और रोजगार, शहरी व ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है तथा ग्रामीण विकास व जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भौतिक पूंजी संचय के बजाय आजकल व्यवहार में पूंजी स्टॉक की वृद्धि को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। जो पूर्णतः मानव संसाधन विकास पर निर्भर करता है। मानव संसाधन विकास देश के निवासियों को आय, कुशलता एवं क्षमता बढ़ानेकी एक प्रक्रिया है। आर्थर लुइस का कहना है कि आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों कापरिणाम है। यह बात सही है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास उसकी कार्यकुशलतातथा प्रशिक्षित श्रमशक्ति पर निर्भर करता हैं। मानव विकास के लिए सरकार द्वारा सृजनात्मक कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के मानव विकास के कार्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्यांकि मानवीय विकास एक वृहद् अवधारणा है। अतः इसके अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों व इनसें सम्बन्धित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Prabhu K.S. (1992), *Regional Dimensions o f Human Development in India,* University ofBombay, Bombay.
2. Tilak, J.B.G, (1991), Human Development Index for India, Indian Association o f SocialSciences Institutions Quarterly, Vol. 10, No.2, pp. 132-138.
3. Government of Rajasthan (2002), Rajasthan Human Development Report 2002, Government of Rajasthan, Jaipur.
4. India Human Development Report (2011), Oxford University Press, New Delhi 110001, India.
5. UNDP (2010): Human Development Report 2010 The Real Wealth of Nations: Pathways to HumanDevelopment, New York.
6. Rajasthan Playing toits Strengths ,A Strategy for Sustained andInclusive Growth, Rajasthan Report,2008
7. http://plan.rajasthan.gov.in/content/planning-portal/en/des.html#

❖◆❖